

# आश्रय गृह में नहीं इंतजाम, बेघर परेशान

बेड व विस्तर की कमी से कड़ाके की ठंड में ठिठुरने को हैं मजबूर, कई साल से कंबलों की नहीं हुई धुलाई

मोहम्मद साकिब • जागरण

नई दिल्ली: हाड़ कंपा देने वाली सर्दी, फटे टेंट से टपकती ओस, दरवाजों की टूटी जालियाँ और फटे पुराने कंबल, यह हाल है मध्य जिले के आश्रय गृहों का। इन आश्रय गृहों को सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले बेघर लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, ताकि कड़ाके की सर्दी में बेघरों को सुकून की छत मिले, लेकिन इन आश्रय गृहों में सुविधाओं के नाम पर खानापूरी की जा रही है। कहीं बेड की व्यवस्था नहीं है तो कहीं सालों से कंबल की धुलाई तक नहीं हुई है। कहीं आश्रय गृहों के शौचालय महज शोपीस बने हुए हैं। सबसे बदतर हालात तो महिलाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृहों की है। यहां गंदा पानी बेघर महिलाओं के लिए मुसीबत बना हुआ है।

टेंट में छेद से टपकती हैं ओस की बूंदें: आसफ अली रोड पर बने आश्रय स्थल में 20 बेड की सुविधा है, जहां 22 बेघर लोग रहते हैं। केयर टेकर अजीम ने बताया कि यहां पर्याप्त संख्या में कंबल की व्यवस्था नहीं है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि टेंट में जगह-जगह छेद हो गए हैं, जिससे रात में ओस की बूंदें टपकती रहती हैं। इन बूंदों से कंबल व बिस्तर गीले हो जाते हैं और वर्षा के दौरान तो इसके गिरने का भी खतरा मंडराता रहता है। यहां आग बुझाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण रखे दिखे, लेकिन वह भी सिर्फ दिखावे के लिए हैं, क्योंकि इन फायर बकेट में आग बुझाने के लिए रेत ही नहीं थी।

महिला आश्रय गृह में समस्याओं का अंधार: जामा मस्जिद के मीना बाजार में बने महिला आश्रय गृह में 30 बेड की सुविधा की गई है, लेकिन यहां 50 से अधिक बेघर महिलाएं अपने बच्चों के साथ रह



एलएन अस्पताल के सामने बने आश्रय गृह में मात्र पांच बेड की ही सुविधा • जागरण



आसफ अली रोड बने आश्रय गृह में फटे टेंट से टपकती हैं ओस की बूंद • जागरण

## एनएचआरसी सदस्य ने अव्यवस्था पर मुख्य सचिव को लिखा पत्र

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को 30 दिसंबर को रैन बसेरों के औचक निरीक्षण के बाद पता चला था कि कड़ाके की ठंड में बेघर लोग कष्ट झेल रहे हैं। एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूनगो ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र भेजा, जिसमें तत्काल उपाय करने और सात दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है।



एलएन के सामने बने आश्रय गृह के शौचालय बने हुए हैं शोपीस • जागरण

रही हैं। यहां लगे अधिकतर बेड पर बिस्तर ही नहीं था और आश्रय गृह के बाहर गंदा पानी जमा है। केयर टेकर रोमा यादव ने बताया कि छह महीने से सीवर का पानी जमा है, इससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। उन्होंने बताया कि वे बेड बढ़ाने

व शौचालयों में पानी की फिटिंग के लिए शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती।

लाइट की नहीं सुविधा, अंधेरे में कर रहे गुजारा: मीना बाजार में बने सबसे बड़े आश्रय गृह में 100 बेड की व्यवस्था है, जिसमें परिवार

## दस्वाजों की टूटी जालियां, सर्द हवा छुड़ा रही कंपकंपी

एलएन अस्पताल के सामने बने आश्रय गृह के दरवाजों की जालियां टूटी हुई मिलीं, जिससे सर्द हवा यहां रह रहे लोगों को ठिठुरने को मजबूर कर देती है। यहां के केयर टेकर राम मोहन ने बताया कि यहां 25 बेघर लोग रहते हैं, जिनके लिए मात्र सात बेड की ही सुविधा है, बाकी लोग जमीन पर सोने को मजबूर हैं। अंदर पानी की डिस्पेंसर मशीन लगी है, जिसमें गर्म पानी ही नहीं आता। यहां का शौचालय साल भर से शोपीस बना हुआ है, जिसमें पानी की सुविधा ही नहीं है।

समेत 150 बेघर लोग रह रहे हैं। आश्रय गृह में लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं मिली और अधिकतर लाइटें खराब हैं। इसके अलावा 150 लोगों के लिए आठ शौचालय बने हैं, जिसमें चार अव्यवस्था के चलते बंद हैं। केयर टेकर याकूब ने

## एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे अधिकारी

सोफिया एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी एनजीओ के जिम्मे इन आश्रय गृहों का रखरखाव है। इसके संचालक सोहेल ने बताया कि उनकी जिम्मेदारी स्टाफ उपलब्ध कराने की है, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के चीफ इंजीनियर वीएस फोनिया ने फोन पर बताया कि कंबल का वतरण हो रहा है। उन्होंने अव्यवस्था पर जूसिब के नाइट शेल्डर डायरेक्टर राजबीर सिंह पर जिम्मेदारी डालकर फोन काट दिया।

बताया कि वह वर्ष 2014 से यहां सेवाएं दे रहे हैं। यहां लोगों को चार शौचालय से ही काम चलाना पड़ रहा है, जिससे काफी समस्या रहती है। यहां पर्याप्त संख्या में कंबल तो थे, लेकिन बेडों की संख्या कम थी। लोगों को परेशानी होती है।

# बुजुर्ग की आत्महत्या मामले का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बेंगलुरु में आयुष्मान योजना में इलाज का लाभ देने से इन्कार करने पर एक वरिष्ठ नागरिक के आत्महत्या करने के मामले में मीडिया में आई खबर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने कर्नाटक के मुख्य सचिव व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने केंद्र सरकार से रिपोर्ट में कर्नाटक सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत

आयुष्मान योजना में इलाज से इन्कार पर आयोग ने चार हफ्ते में मांगी रिपोर्ट

बेंगलुरु के अस्पताल ने योजना में पंजीकृत वृद्ध को किया था मना

प्रधानमंत्री जन आरोग्य वरिष्ठ नागरिक योजना (एबीपीएमजेएवाइ) लागू होने की वर्तमान स्थिति भी बताने को कहा है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पांच लाख तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। हाल ही में यह योजना सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी लागू की गई है।

## खुदकुशी मामले में मानवाधिकार आयोग ने कर्नाटक से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 9 जनवरी (ब्यूरो)।

एक बुजुर्ग नागरिक द्वारा सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज न किए जाने से दुखी होकर खुदकुशी करने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्र सरकार ने 70 साल से ज्यादा उम्र वाले सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की है। इस बुजुर्ग नागरिक को बैंगलोर के सरकारी अस्पताल ने योजना के तहत उपचार सुविधा देने से इनकार कर दिया था। दुखी होकर उसने 25 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी।



## **NHRC Takes Note Of Suicide By Senior Citizen After 'Denied' Treatment Under Ayushman Scheme By Govt Hospital**

<https://www.timesnownews.com/india/nhrc-takes-note-of-suicide-by-senior-citizen-after-denied-treatment-under-ayushman-scheme-by-govt-hospital-article-117093491>

Panel issues notices to Health & Family Welfare Ministry Secretary and Chief Secretary, Government of Karnataka calling for report in four weeks.

**Authored by:** [Harish V Nair](#) Updated Jan 9, 2025, 22:30 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday took suo motu cognizance of a media report that a 72-year-old man committed suicide on 25th December, 2024, as the State Government-run Kidwai Memorial Institute of Oncology in Bengaluru, Karnataka declined to provide him Rs. 5 lakh cover under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) for which he had enrolled himself.

Reportedly, the hospital denied him the benefit of the scheme to the senior citizens stating that the State government orders in this regard had not arrived yet.

A few more cases regarding the problems being faced by the beneficiaries of the AB PM-JAY scheme for senior citizens have also been mentioned in the news report.

The Commission led by its Chairperson Justice V Ramasubramanian has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) senior citizen scheme has been framed with an aim to ensure good medical care for senior citizens, especially those who are not able to spend the hospital bills and cost of specialized treatment and medicines. If senior citizens are not getting the benefit of the scheme intended for their welfare, it may amount to violation of their right to health, which is inherent to a life with dignity, noted the Commission.

Accordingly, the Commission has issued notices to the Secretary, Union Ministry of Health & Family Welfare, and the Chief Secretary, Government of Karnataka calling for a detailed report on the matter within four weeks. The reports are expected to include the present status of the implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) senior citizen scheme in Karnataka and other States/ Union Territories.

## **NHRC takes suo motu cognizance of senior citizen's suicide due to denial of AB PM-JAY treatment in Bengaluru**

<https://www.aninews.in/news/national/general-news/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-senior-citizens-suicide-due-to-denial-of-ab-pm-jay-treatment-in-bengaluru20250109223926/>

ANI | Updated: Jan 09, 2025 22:39 IST

New Delhi [India], January 9 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a tragic incident where a 72-year-old man reportedly committed suicide on December 25 last year after being denied treatment under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) at a government-run hospital in Bengaluru, Karnataka.

The victim, enrolled in the AB PM-JAY scheme, sought medical treatment at the Kidwai Memorial Institute of Oncology but was denied coverage due to the alleged lack of state government orders, despite his eligibility. The denial of treatment under the scheme, which is designed to provide senior citizens with financial coverage for medical care, was reportedly cited as the reason for the man's tragic decision to take his own life.

This incident follows reports of similar issues faced by senior citizens in other hospitals across the state, where they were denied benefits under the scheme. The NHRC has expressed grave concern over the "violation of human rights" if the reports are true. The AB PM-JAY scheme is specifically intended to ensure that senior citizens, particularly those who cannot afford costly medical treatments, receive timely and adequate healthcare.

A failure to provide benefits under this scheme undermines their right to health and dignity, which is intrinsic to the right to life. In response, the NHRC has issued notices to the Secretary of the Union Ministry of Health and Family Welfare and the Chief Secretary of the Government of Karnataka.

The Commission has called for a detailed report on the matter within four weeks, which should include the current status of the AB PM-JAY scheme's implementation in Karnataka, as well as in other States and Union Territories across India. The Commission has emphasized the urgency of addressing these issues, which affect the welfare and well-being of vulnerable senior citizens across the country. (ANI)

## **NHRC issues notice to Karnataka over treatment denial under ABPM-JAY**

<https://www.deccanherald.com/india/karnataka/nhrc-issues-notice-to-karnataka-over-treatment-denial-under-abpm-jay-3348779>

The state-run Kidwai Memorial Institute of Oncology in Bengaluru, declined to provide a man Rs 5 lakh cover under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY), for which he had enrolled himself.

DHNSLast Updated : 10 January 2025, 05:30 IST

New Delhi: The National Human Rights Commission has taken suo motu cognisance of the reported suicide by a senior citizen due to denial of treatment under ABPM-JAY scheme by a government-run hospital in Bengaluru and has issued notices to the Union Ministry of Health and the Karnataka government.

“The Commission issued notices to the Secretary, Union Ministry of Health & Family Welfare, and the Chief Secretary, Government of Karnataka calling for detailed reports within four weeks. The report to include the present status of the implementation of the ABPM-JAY scheme in Karnataka and other States/Union Territories,” a statement from the Commission said on Thursday. The state-run Kidwai Memorial Institute of Oncology in Bengaluru, declined to provide him Rs 5 lakh cover under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY), for which he had enrolled himself.

The hospital denied benefit of the scheme to the senior citizens stating that the state government orders in this regard had not arrived yet. A few more cases regarding problems being faced by the beneficiaries of AB PM-JAY scheme for senior citizens have also been mentioned in the news report, the statement said.

The Commission has observed that the contents of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights. The ABPM-JAY senior citizen scheme has been framed with an aim to ensure good medical care for senior citizens, especially those who are not able to meet the hospital bills and cost of specialised treatment and medicines.

If senior citizens are not getting the benefit of the scheme intended for their welfare, it may amount to violation of their right to health, which is inherent to a life with dignity, the statement added.

## **NHRC Probes Human Rights Violation in Senior Health Scheme Denial**

<https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3220564-nhrc-probes-human-rights-violation-in-senior-health-scheme-denial>

The NHRC has taken action against the Centre and Karnataka government following reports of a 72-year-old man's suicide after allegedly being denied welfare benefits by a hospital. The NHRC seeks a detailed report on the implementation of the Ayushman Bharat scheme, highlighting potential human rights violations.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 09-01-2025 20:52 IST | Created: 09-01-2025 20:52 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has intervened following allegations that a 72-year-old man took his life after being denied benefits under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana by a Karnataka state-run hospital. The NHRC stated that the incident could constitute a serious violation of human rights.

In response to the media report, the NHRC issued notices to the Union Ministry of Health and Family Welfare and the Karnataka government. The commission has requested a comprehensive report on the senior citizen scheme's current implementation status in Karnataka and across other regions within four weeks.

The commission emphasized that the denial of such health benefits raises broader concerns regarding the rights of senior citizens to access necessary medical care, which is integral to their dignity and well-being. Additional cases of similar denials have also been mentioned, urging a reevaluation of the scheme's effectiveness.

## **NHRC Probes Ayushman Bharat Denial After Tragic Suicide**

<https://www.devdiscourse.com/article/headlines/3220737-nhrc-probes-ayushman-bharat-denial-after-tragic-suicide>

The National Human Rights Commission is investigating the denial of treatment under Ayushman Bharat, which led a 72-year-old man to commit suicide. The incident raises concerns about human rights violations and the scheme's implementation for senior citizens. NHRC seeks detailed reports from relevant authorities.

[Devdiscourse News Desk](#) | Updated: 09-01-2025 22:45 IST | Created: 09-01-2025 22:45 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has launched an investigation into a distressing incident involving a 72-year-old man who reportedly took his own life on December 25, after being denied treatment under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) at a government hospital in Bengaluru, Karnataka.

The victim, an enrollee in the AB PM-JAY, was allegedly refused medical coverage at the Kidwai Memorial Institute of Oncology due to a supposed lack of state government directives, despite being eligible. This denial of service under a scheme intended to provide financial medical aid to senior citizens, was linked to the man's tragic decision.

Expressing profound concern over potential human rights violations, the NHRC noted that the AB PM-JAY scheme aims to deliver essential healthcare to senior citizens who cannot afford expensive medical treatments. In light of the incident, the NHRC has issued notices to the Union Ministry of Health and Family Welfare and the Government of Karnataka, demanding a comprehensive report within four weeks about the scheme's implementation statewide and nationally.



## **NHRC to Probe Death After Denial of Treatment Under Ayushman Bharat**

<https://en.themooknayak.com/health/nhrc-to-probe-death-after-denial-of-treatment-under-ayushman-bharat>

Commission launches investigation into alleged suicide case in Bengaluru

09 Jan 2025, 11:49 pm

New Delhi– The National Human Rights Commission (NHRC) is launching an investigation into the death of a 72-year-old man in Bengaluru who allegedly committed suicide after being denied treatment under the Ayushman Bharat scheme.

The man, identified only as a senior citizen, died on December 25 after being refused treatment at the state-run Kidwai Memorial Institute of Oncology. According to media reports, the hospital denied the man's Rs 5 lakh Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) coverage, claiming they were awaiting state government orders regarding the scheme.

The NHRC expressed serious concerns over the incident, stating that it could represent a violation of human rights. The Commission highlighted additional media reports alleging other beneficiaries have faced issues accessing the AB PM-JAY senior citizen scheme.

The NHRC has issued notices to the Secretary of the Union Ministry of Health & Family Welfare and the Chief Secretary of Karnataka, demanding a detailed report within four weeks. The report should include the status of the Ayushman Bharat scheme's implementation in Karnataka and other states and territories.

The NHRC emphasized the scheme's objective to provide affordable healthcare to senior citizens, particularly those unable to afford treatment costs. The Commission underscored that denying eligible individuals access to these benefits could infringe upon their right to health and a dignified life.

## NHRC ने AB PM-JAY उपचार से इनकार किए जाने के कारण वरिष्ठ नागरिक की आत्महत्या का स्वतः संज्ञान लिया

<https://jantaserishta.com/delhi-ncr/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-senior-citizens-suicide-over-denial-of-ab-pm-jay-treatment-3758330>

**Gulabi Jagat 9 Jan 2025 6:33 PM GMT**

**New Delhi:** राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( एनएचआरसी ) ने एक दुखद घटना का स्वतः संज्ञान लिया है जहां एक 72 वर्षीय व्यक्ति ने पिछले साल 25 दिसंबर को कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सरकारी अस्पताल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई ) के तहत इलाज से इनकार करने के बाद आत्महत्या कर ली थी। एबी पीएम-जेएवाई योजना में नामांकित पीड़ित ने किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी में चिकित्सा उपचार की मांग की, लेकिन पात्रता के बावजूद, राज्य सरकार के आदेशों की कथित कमी के कारण कवरेज से इनकार कर दिया गया। वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा देखभाल के लिए वित्तीय कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई योजना के तहत उपचार से इनकार करना कथित तौर पर आदमी के खुद की जान लेने के दुखद फैसले का कारण बताया गया था।

यह घटना राज्य भर के अन्य अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सामना किए जाने वाले इसी तरह के मुद्दों की रिपोर्ट के बाद हुई है, जहां उन्हें योजना के तहत लाभ से वंचित किया गया था। एनएचआरसी ने रिपोर्ट के सच होने पर "मानव अधिकारों के उल्लंघन" पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। एबी पीएम-जेएवाई योजना का उद्देश्य विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक, विशेष रूप से वे जो महंगे चिकित्सा उपचार का खर्च नहीं उठा सकते हैं, उन्हें समय पर और पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा मिले। इस योजना के तहत लाभ प्रदान करने में विफलता उनके स्वास्थ्य और सम्मान के अधिकार को कमजोर करती है, जो जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है।

जवाब में, एनएचआरसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किए हैं। आयोग ने चार सप्ताह के भीतर मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसमें कर्नाटक के साथ-साथ पूरे भारत में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एबी पीएम-जेएवाई योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति शामिल होनी चाहिए । आयोग ने इन मुद्दों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है, जो देश भर में कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और भलाई को प्रभावित करते हैं। (एनआई)

## एनएचआरसी ने बुजुर्ग के 'आत्महत्या' करने के मामले में केंद्र, कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया

<https://www.abc24.in/country/nhrc-issues-notices-to-centre-karnataka-govt-over-elderly-mans-suicide-2888182.html>

Edited By :Bhasha Modified Date: January 10, 2025 / 12:09 AM IST

Published Date: January 10, 2025 12:09 am IST

नयी दिल्ली, नौ जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने केंद्र और कर्नाटक सरकार को उन खबरों पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि पिछले साल दिसंबर में बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल द्वारा कल्याणकारी योजना का लाभ देने से इनकार करने पर 72 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

एनएचआरसी ने कहा कि अगर खबर की सामग्री सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट में कर्नाटक, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी शामिल किए जाने की भी उम्मीद है।

एनएचआरसी ने कहा कि उसने 'मीडिया में आई एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है कि 72 वर्षीय व्यक्ति ने 25 दिसंबर, 2024 को आत्महत्या कर ली, क्योंकि कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य सरकार द्वारा संचालित किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये का कवर देने से इनकार कर दिया।'

## पढ़ाई में अच्छे अंक लाने का दबाव और माता-पिता से बेहतर संवाद नहीं होने के चलते घरों से भागते हैं...

<https://www.livehindustan.com/ncr/new-delhi/story-teen-runaways-on-the-rise-nhrc-study-reveals-causes-and-statistics-201736426439449.html>

प्रभात कुमार नई दिल्ली। माता-पिता के साथ बेहतर संवाद की कमी, पढ़ाई में अच्छे अंक

Newsrap हिन्दुस्तान, नई दिल्ली Thu, 9 Jan 2025 06:10 PM

माता-पिता के साथ बेहतर संवाद की कमी, पढ़ाई में अच्छे अंक लाने का दबाव और आजादी की कमी करने कारण किशोर उम्र के बच्चे घर से भाग रहे हैं। इतना ही नहीं, किशोरों से दो गुणा से भी अधिक किशोरियां घरों से लापता हो रही है। इसका, खुलासा भारतीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा कराए गए एक शोध में हुआ है। शोध में यह भी खुलासा किया गया है कि भागने के बाद जब बच्चे घर वापस लौटते हैं तो उनमें से 25 फीसदी स्कूल जाना बंद कर देते हैं। लड़कों की तुलना में अधिक लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया।

शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चों के लापता होने के कई कारणों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि किशोर उम्र के बच्चे प्रेम संबंध, साथियों के प्रभाव, पढ़ाई से संबंधित दबाव और घर में बहस विवाद के चलते घर से भागते हैं। इसमें कहा गया है कि आंकड़ों का गुणात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि पढ़ाई में अच्छे अंक लाने के दबाव, शारीरिक दंड, स्वतंत्रता की कमी के कारण बच्चों में अपने माता-पिता के प्रति नाराजगी की भावना विकसित हो जाती है। इसी वजह से उनमें घर से भागने की भावना विकसित होती है। शोध में यह भी पाया गया है कि साथियों माता-पिता के साथ बेहतर संवाद नहीं होने या किसी बात पर विवाद होने के चलते भी बच्चों में घर से भागने की भावना विकसित हो जाती है। मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर न्यू कॉन्सेप्ट सेंटर फॉर डेवलपमेंट कम्प्यूनिकेशन, नई दिल्ली द्वारा किए गए इस शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि घर से लापता होने वाले किशोरियों की औसत आयु 16 वर्ष पाई गई है, जबकि किशोरों की औसत आयु 14.5 साल है। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लापता बच्चों में से 71 फीसदी लड़कियां और 29 फीसदी लड़के थे। शोध रिपोर्ट में 2021 के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। हाल ही में मानवाधिकार आयोग द्वारा सार्वजनिक की इस रिपोर्ट के अनुसार किशोरावस्था की शुरुआत में ज्यादा लड़के लापता हुए, जबकि किशोरावस्था के मध्य में लड़कियों के लापता होने की संख्या अधिक है। इसी प्रकार, मिडिल स्कूल में लड़कों के लापता होने की घटना लड़कियों की तुलना में दोगुनी थी जबकि हाईस्कूल जाने के वर्षों में लड़कियों के लापता होने की घटना 15 फीसदी अधिक देखी गई। शोध में बच्चों के लापता होने के कारणों का पता लगाने के लिए दिल्ली से भागे बच्चों से जुड़े मामले का अध्ययन किया गया। इसमें प्रश्नावली के आधार पर बच्चों के साक्षात्कार को भी शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 51 फीसदी बच्चे अपने स्कूल या ट्यूशन के | वायरल खबरें घर पर बीवी को ही निहारोगे, संडे को भी उयूटी करो, बिजनेसमैन सुब्रह्मण्यन की सलाह महिला ने भरे एयरपोर्ट पर खींची मौलाना की पगड़ी, वजह जान हैरान रह जाएंगे आप प्रेग्रेट सीमा हैदर को क्यों मारने लगा सचिन, फिर दिखा दोनों में रोमांस:

VIDEO आग खिलाना, बंद आंख से कुदवाना, कर्मियों पर ऐसे प्रयोग क्यों कर रही चीनी कंपनियां आने-जाने के समय भाग ते हैं।

### प्रमुख आंकड़े

- शोध में शामिल किए गए दिल्ली में लापता होने को लेकर दर्ज मुकदमों के विश्लेषण के आधार पर कहा गया है कि भागने वालों में 25 फीसदी बच्चे बीच में ही स्कूली पढ़ाई छोड़ चुके थे और इनमें से अधिकांश 81 फीसदी लड़कियां थीं।

- भागने वालों में बच्चों में: 83 फीसदी हिंदू जबकि 13 फीसदी मुस्लिम। इसी तरह लगभग 64 फीसदी बच्चे सामान्य श्रेणी के थे, 20 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 9 फीसदी अनुसूचित जाति (एससी) और 3 फीसदी अनुसूचित जनजाति (एसटी) के थे।

- 89 फीसदी मामलों में, बच्चे के माता-पिता दोनों जीवित थे और बच्चे के साथ रह रहे थे। दिल्ली से लापता हुए 59 फीसदी बच्चों का नम दिल्ली में हुआ था। साक्षात्कार में शामिल 60 फीसदी माता-पिता ने बताया कि वे प्रवासी थे।

किस उम्र में कितने बच्चे हो रहे हैं लापता

28 फीसदी बच्चे लापता होने के समय 16 वर्ष की आयु के थे।

23 फीसदी बच्चे 17 वर्ष की आयु के थे।

लापता होने के समय 32 फीसदी लड़कियों की उम्र 16 वर्ष थीं, जबकि 25 फीसदी लड़के लापता होने के समय उम्र 14 वर्ष था। बेहतर पेरेंटिंग कार्यक्रम के जरिए बच्चों में घर से भागने के जोखिम को किया जा सकता है कम रिपोर्ट में कहा गया है कि परिवार आधारित पेरेंटिंग कार्यक्रम कई चिंताओं को संबोधित कर सकते हैं जिससे माता-पिता और किशोरों दोनों के लिए बेहतर परिणाम और जीवनशैली प्राप्त हो सकती है, जिससे बच्चों के अपराधी व्यवहार को अपनाने या भागने का जोखिम कम हो सकता है। ऐसे कार्यक्रम जो पारिवारिक संबंधों को मजबूत करते हैं और पेरेंटिंग कौशल में सुधार करते हैं, वे युवाओं की समस्याओं को संबोधित करने के लिए प्रभावी रणनीतियां हो सकती हैं। इसके लिए माता-पिता के कौशल प्रशिक्षण, विशेष रूप से सकारात्मक बातचीत, समूह निर्माण, तनाव प्रबंधन, क्रोध से निपटना, हास्य का उपयोग करके वांछित व्यवहार को प्रोत्साहित करना, उचित परिणाम और सकारात्मक ध्यान और सुदृढ़ीकरण आदि विषयों प्रशिक्षण दिया जा सकता है।



## Jalandhar Civil Hospital staff 'dump' man outside Raen Basera, readmitted by shopkeepers

<https://www.tribuneindia.com/news/jalandhar/jalandhar-civil-hospital-staff-dump-man-outside-raen-basera-readmitted-by-shopkeepers/>

Association members write to **NHRC**, DC; seek probe; second case in two months

Aparna Banerji Tribune News Service Updated At : 04:31 AM Jan 10, 2025 IST

After the recent uproar over two men being abandoned outside the Raen Basera (night shelter) under the Domoriah Bridge in Jalandhar on November 23, the Civil Hospital staff have again come under attack by residents over the similar plight of another patient in January this year.

Members of the Sant Cinema Shopkeepers Association have written to the National Human Rights Commission as well as the DC, Jalandhar, demanding an inquiry and action against the erring staff of the hospital regarding a patient, who was allegedly abandoned outside the night shelter (under Domoriah bridge) on the night of January 6. The association members got the patient admitted again the same night.

Shop owners have questioned the repeated abandoning of patients outside the night shelter in the extreme cold winter.

As per the complaint by the shopkeepers' association, a patient, Raja Babu, had been under treatment at the hospital but was dropped outside the Raen Basera under the Domoriah Bridge in Jalandhar by the hospital staff on the night of January 6. The complaint states that the ailing man was unable to walk and was appealing to be taken back to the hospital again.

According to the patient, he had been admitted to the hospital for two months. The complaint argues that contrary to the claims that he left the Civil Hospital himself, the man was unable to walk. Similarly, two men Anmol And Vijay had also been dropped outside the Raen Basera in November.

The complaint says, "The act of the hospital is inhumane. We demand that the matter be inquired into and the erring hospital staff be acted against."

While Raja Babu was taken to the Civil Hospital by members of the shopkeepers association on the night of January 6 itself (where he is currently under treatment), the members also submitted a memorandum to the DC on the issue on January 7. Previously, too, in the November 2024 case, the shopkeepers' association had taken the two men to the hospital, where one of them had subsequently died.

A video of Raja Babu was shared on social media where the scantily clad elderly man sits wrapped in a blanket by the roadside and says he can't eat or get up.

Shopkeeper Lalit Mehta said, "These kind of cases last happened in 2020 and are happening again since November 2024. This man was left at 7 pm, he was sick and miserable. Unable to walk, he would have died if left unattended in the night. We called the 108 ambulance on the night of January 6 itself and took him back to the hospital, where I accompanied him in a car. I got his file made only after which I returned. Till 1 am, the police also kept calling me for details. The biggest question is who dropped an infirm, under-treatment patient in the open on a December night, and why?"

Civil Surgeon Gurmeet Lal said, "As per staff, the patient went from the Civil Hospital himself without informing the staff. Also, repeatedly in such cases, these patients are found to be on their own, with no attendants or family members. At times, they are abandoned by someone who later vanishes. We are aware of such cases and through links with the District Social Security Officer, we are working to find a more concrete solution to such cases."

## **NHRC takes suo motu cognisance of senior citizen's suicide due to denial of Ayushman Bharat scheme treatment**

<https://www.thip.media/news/nhrc-takes-suo-motu-cognisance-of-senior-citizens-suicide-due-to-denial-of-ayushman-bharat-scheme-treatment/97676/>

Team THIP Last Updated on January 9, 2025 by

New Delhi, Jan 9 (IANS) The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of an incident from Karnataka, where a 72-year-old man committed suicide on December 25 after a public hospital in Bengaluru declined to provide him [treatment](#) under the Ayushman Bharat scheme.

As per a media report, the state-run Kidwai Memorial Institute of Oncology had denied him the benefit of Rs 5 lakh cover to the senior citizens under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) for which he had enrolled himself, stating that state government orders in this regard had not arrived yet.

Observing that the contents of the media report, if true, raised a serious issue of violation of human rights, the Commission said that a few more cases regarding the problems being faced by the beneficiaries of the AB PM-JAY scheme for senior citizens have also been mentioned in the news report.

Taking suo moto cognisance of the matter, the NHRC has issued notices to the Secretary of the Union Ministry of Health & Family Welfare and the Chief Secretary of Karnataka and called for a detailed report on the matter within four weeks.

It said that the reports are expected to include the present status of the implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) senior citizen scheme in Karnataka and other states and Union Territories.

The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) senior citizen scheme has been framed with an aim to ensure good medical care for senior citizens, especially those who are not able to spend the hospital bills and cost of specialised treatment and medicines.

“If senior citizens are not getting the benefit of the scheme intended for their welfare, it may amount to a violation of their right to health, which is inherent to a life with dignity,” the NHRC said.

–IANS

pds/vd

## **India News | NHRC Takes Suo Motu Cognizance of Senior Citizen's Suicide Due to Denial of AB PM-JAY Treatment in Bengaluru**

<https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-senior-citizens-suicide-due-to-denial-of-ab-pm-jay-treatment-in-bengaluru-6553270.html>

Get latest articles and stories on India at LatestLY. The victim, enrolled in the AB PM-JAY scheme, sought medical treatment at the Kidwai Memorial Institute of Oncology but was denied coverage due to the alleged lack of state government orders, despite his eligibility.

New Delhi [India], January 9 (ANI): The National Human Right ..

New Delhi [India], January 9 (ANI): The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a tragic incident where a 72-year-old man reportedly committed suicide on December 25 last year after being denied treatment under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) at a government-run hospital in Bengaluru, Karnataka. The victim, enrolled in the AB PM-JAY scheme, sought medical treatment at the Kidwai Memorial Institute of Oncology but was denied coverage due to the alleged lack of state government orders, despite his eligibility.

The denial of treatment under the scheme, which is designed to provide senior citizens with financial coverage for medical care, was reportedly cited as the reason for the man's tragic decision to take his own life. This incident follows reports of similar issues faced by senior citizens in other hospitals across the state, where they were denied benefits under the scheme.

The NHRC has expressed grave concern over the "violation of human rights" if the reports are true. The AB PM-JAY scheme is specifically intended to ensure that senior citizens, particularly those who cannot afford costly medical treatments, receive timely and adequate healthcare. A failure to provide benefits under this scheme undermines their right to health and dignity, which is intrinsic to the right to life. In response, the NHRC has issued notices to the Secretary of the Union Ministry of Health and Family Welfare and the Chief Secretary of the Government of Karnataka. The Commission has called for a detailed report on the matter within four weeks, which should include the current status of the AB PM-JAY scheme's implementation in Karnataka, as well as in other States and Union Territories across India. The Commission has emphasized the urgency of addressing these issues, which affect the welfare and well-being of vulnerable senior citizens across the country. (ANI)

## India News | NHRC Notice to Centre, K'taka Govt over 'suicide' by Old Man over Hospital 'denying' Scheme Benefit

<https://www.latestly.com/agency-news/india-news-nhrc-notice-to-centre-ktaka-govt-over-suicide-by-old-man-over-hospital-denying-scheme-benefit-6553047.html>

*Get latest articles and stories on India at LatestLY. The NHRC on Thursday said it has issued a notice to the Centre and the Karnataka government over reports that a 72-year-old man allegedly committed suicide in December last year after a state-run hospital in Bengaluru "denied" him the benefit of a welfare scheme.*

New Delhi, Jan 9 (PTI) The NHRC on Thursday said it has issued a notice to the Centre and the Karnataka government over reports that a 72-year-old man allegedly committed suicide in December last year after a state-run hospital in Bengaluru "denied" him the benefit of a welfare scheme. The National Human Rights Commission (NHRC) has observed that the content of the media report, if true, raises a serious issue of violation of human rights.

Accordingly, the NHRC has issued notices to the secretary, Union Ministry of Health and Family Welfare, and the chief secretary, Karnataka government, seeking a detailed report within four weeks, it said in a statement. The reports are expected to include the present status of the implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) senior citizen scheme in Karnataka and other states and Union Territories, the statement said.

The NHRC said it has "taken suo motu cognisance of a media report that a 72-year-old man committed suicide on 25th December, 2024, as the state government-run Kidwai Memorial Institute of Oncology in Bengaluru, Karnataka, declined to provide him Rs 5 lakh cover under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) for which he had enrolled himself". Reportedly, the hospital "denied him the benefit of the scheme to the senior citizens" stating that the state government orders in this regard "had not arrived yet", the rights panel said in the statement.

A few more cases regarding the problems being faced by the beneficiaries of the AB PM-JAY scheme for senior citizens have also been mentioned in the news report, it added. The AB PM-JAY senior citizen scheme has been framed with an aim to ensure good medical care for senior citizens, especially those who are not able to foot the hospital bills and cost of specialised treatment and medicines, it said. "If senior citizens are not getting the benefit of the scheme intended for their welfare, it may amount to violation of their right to health, which is inherent to a life with dignity," the statement said.



## **Mizoram establishes 'Widow Cell' to empower and protect rights of widows**

<https://www.indiatodayne.in/mizoram/story/mizoram-establishes-widow-cell-to-empower-and-protect-rights-of-widows-1152157-2025-01-09>

In a significant step toward empowering widows and safeguarding their rights, Mizoram's Social Welfare & Tribal Affairs, Women and Child Development Minister Lalrinpuii inaugurated the 'Widow Cell' on Thursday, January 9 at her office. This initiative positions Mizoram among the select Indian states to adopt such a progressive measure

Ezrela Dalidia Fanai Jan 09, 2025, Updated Jan 09, 2025, 7:27 PM IST

In a significant step toward empowering widows and safeguarding their rights, Mizoram's Social Welfare & Tribal Affairs, Women and Child Development Minister Lalrinpuii inaugurated the 'Widow Cell' on Thursday, January 9 at her office. This initiative positions Mizoram among the select Indian states to adopt such a progressive measure.

The establishment of the Widow Cell aligns with the National Human Rights Commission's (NHRC) recommendation urging governments at the central, state, and union territory levels to create dedicated cells for widows. These cells, integrated into the One Stop Centers in each district, aim to ensure the protection and welfare of widows across the state.

Minister Lalrinpuii emphasized that the Widow Cell seeks to enhance existing welfare initiatives and devise comprehensive plans for widows' futures. She underscored the importance of widows' care as a collective responsibility, both nationally and within communities. The Widow Cell is envisioned as a vital tool to safeguard widows' rights, provide solace, and offer guidance to those in need.

The Widow Cell's objectives include providing skill development training for unemployed widows, disseminating information about government welfare schemes, offering psychological counseling tailored to individual needs, and delivering legal support to uphold their rights under the law.

## आयुष्मान भारत का लाभ नहीं मिलने पर बेंगलुरु में बुजुर्ग ने की आत्महत्या, एनएचआरसी ने जारी किया नोटिस

<https://livevns.news/National/nhrc-notice-ayushman-bharat-karnatakaph/cid16028003.htm>

[https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2025/1/9/NHRC-Notice-Ayushman-Bharat-Karnataka.php#google\\_vignette](https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2025/1/9/NHRC-Notice-Ayushman-Bharat-Karnataka.php#google_vignette)

By [Livevns.news Desk](#) Jan 9, 2025, 19:16 IST

नई दिल्ली, 9 जनवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज से इनकार करने के कारण एक वरिष्ठ नागरिक के आत्महत्या करने के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। 25 दिसंबर को बेंगलुरु में राज्य सरकार के किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने 72 वर्षीय व्यक्ति को योजना के तहत मिलने वाला 5 लाख का कवरेज देने से इनकार कर दिया था।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कथित तौर पर अस्पताल ने उन्हें यह कहते हुए वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली योजना का लाभ देने से इनकार कर दिया कि इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश अभी तक नहीं आए हैं। समाचार रिपोर्ट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी पीएम-जेएवाई योजना के लाभार्थियों को होने वाली समस्याओं से संबंधित कुछ और मामलों का भी उल्लेख किया गया है।

आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में कर्नाटक और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) वरिष्ठ नागरिक योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी है।

## **TOI report prompts Centre to act on elders' health scheme issues in K'taka**

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/toi-report-prompts-centre-to-act-on-elders-health-scheme-issues-in-ktaka/articleshow/117095362.cms>

Jan 9, 2025, 11.59 PM IST

### TOI IMPACT

Bengaluru: A day after the Times of India reported the struggles of the ailing elderly, who are being denied benefits of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) despite being enrolled for the scheme due to the failure of the Centre and Karnataka govt to sort out issues regarding sharing the burden, Union minister of health and family welfare JP Nadda is said to have taken cognisance of the issue.

The scheme promises a Rs 5-lakh annual cover to each enrolled senior citizen towards hospitalisation cost.

Nadda is said to have asked Bangalore South MP Tejasvi Surya to give a note to him about the issues in Karnataka, so that he could take it up with his officials.

"I have already spoken to Union health minister JP Nadda and shared the TOI report, and he has asked me to send another note on this so that he can talk to his officials about this," Surya said.

The report, headlined 'Ailing elder denied Rs 5L health cover on hospitals' doorstep', had highlighted how a 72-year-old Bengalurean was traumatised after he was diagnosed with gastric cancer and a hospital denied him the scheme benefits stating that they are yet to get the state govt orders. The senior citizen later died by suicide. Another 87-year-old citizen admitted to hospital too was denied the benefits, citing lack of govt instructions.

Citing a response from the Union govt, Surya's office said: "The govt is committed to sharing 60% of the expenditure at approved rates for the beneficiaries holding Ayushman cards. While the cards are being created and the IT systems are configured, Karnataka govt has not issued instructions to empanelled hospitals in the state to implement the expanded scheme for the card holders. Since no treatment has been given so far, no claims have been raised by hospitals and hence, no funds are to be released by the Centre to Karnataka as of date for treatment given to senior citizens."

Karnataka health and family welfare minister Dinesh Gundu Rao said according to data from Suvarna Arogya Suraksha Trust, the state govt has processed claims worth Rs 710 crore since 2018 for those over 70 years. Citing a letter written to the Centre in Nov

2024, Rao said: "Right now, the calculation which they have worked out is very complicated. And it doesn't help. There are some doubts and we have sent a letter, but they have not even bothered to respond."

Brijesh Chowta, BJP MP from Dakshina Kannada, called it a barbaric disregard of citizens' welfare by denying them their right to health. "On one hand, they dry the state coffers, then go on to burden the common people with a new cess every other day, and on top of that, now are depriving the needy and elderly of the boon called Ayushman Bharat, offered by our PM @narendramodi led central govt, by citing lack of clarity on cost sharing (sic)," he posted on X.

BOX 1

## WAR OF WORDS ONLINE

CM @Siddaramaiah's govt has once again shown disregard for the welfare of Karnataka's senior citizens by denying them access to emergency health treatment under PM Sri @NarendraModiji's Ayushman Bharat scheme. The non-implementation of the scheme highlights the apathy of the Congress govt. This, while it has no qualms in awarding DPRs to consultancy firms for doing a copy-paste job for an unnecessary tunnel road project in Bengaluru and when it is already burdening citizens with fare hikes in every possible sector. Since the launch of the scheme on Nov 1, 2024, around 35.7 crore citizens have enrolled across the country. On a daily basis, in Bengaluru South, my office is enrolling 100-150 eligible seniors and has completed over 2,000 registrations. The denial of treatment is a betrayal of trust of the elderly. Urging state health minister @DineshGRao to rise above party affiliations & implement this scheme

Tejasvi Surya, Bangalore South MP

Don't jump to conclusions too soon Mr @Tejasvi\_Surya. FYI for the Ayushman Bharat-Arogya Karnataka Scheme which should be funded 60:40 between GOI & GOK is actually 25:75. We are contributing 75% of the expenditure. We have written to the Centre last Nov seeking clarification on the scheme. So far, we haven't received any reply. It should not be that the Centre announces a scheme, takes credit and we end up paying for it, like what's happening with AB-ArK. Also, I don't understand why people over 70 need to register and make cards. What is Aadhaar card for? They can simply make use of the Aadhaar or ration card and avail the treatment as is being done under our health scheme in Karnataka. I hope you understand and please join us to ensure that Karnataka doesn't get shortchanged

Dinesh Gundu Rao, Karnataka minister for health and family welfare

box

NHRC notice to Centre, K'taka

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Centre and the Karnataka govt over the TOI report.

NHRC observed that the content of the report, if true, raises a serious issue of violation of human rights. The notice issued to the secretary, Union ministry of health and family welfare, and the chief secretary, Karnataka govt, sought a detailed report within four weeks.

NHRC said it has "taken suo motu cognisance of the media report": A few more cases regarding the problems being faced by the AB PM-JAY beneficiaries have also been mentioned in the news report, it added.

"If senior citizens are not getting the benefit of the scheme intended for their welfare, it may amount to violation of their right to health, which is inherent to a life with dignity," NHRC said in a statement. PTI

box

'Focus on taxpayers' social security'

"It's disappointing that the govt couldn't create a comprehensive health insurance policy that would benefit the people," Sumanth, software engineer, posted on X.

Another user posted: "It's frustrating to see someone who's paid taxes their whole life get no proper social security after retirement. Our hard-earned money is being used for freebies. Isn't it time the govt focused on supporting honest taxpayers."



## **Give ₹1 crore as compensation, government job for kin of deceased in Tirupati stampede: CPM leader**

<https://www.thehindu.com/news/national/andhra-pradesh/give-1-crore-as-compensation-government-job-for-kin-of-deceased-in-tirupati-stampede-cpm-leader/article69081435.ece>

Kandharapu Murali calls the stampede an 'indelible blot' that will remain forever on the TTD and wants an end to the 'VIP culture' prevalent at Tirumala

Published - January 09, 2025 08:36 pm IST - TIRUPATI

Members of Tirupati Poura Sanghala Samakhya, a consortium of civil society organisations, took out a candlelight rally in the city in memory of the deceased devotees involved in the stampede on Thursday.

CPM district leader Kandharapu Murali, who called the stampede an 'indelible blot' that would remain forever on the Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD), demanded ₹1 crore as compensation and government job for the kin of the deceased. He called for an end to the 'VIP culture' prevalent at Tirumala which he alleged led to the demise of the common pilgrims.

Republican Party of India (RPI) president P. Anjaiah, CPI district leader Chinnam Penchalaiah, Congress leader Mangati Gopal Reddy, All India Democratic Women's Association (AIDWA) district secretary P. Sai Lakshmi participated in the rally.

Government blamed

Opposition parties minced no words in blaming the State government as well as the Tirumala Tirupati Devasthanams (TTD) management for 'laxity' in handling the crowd gathered to get the 'Vaikunta Dwara Darshan' tokens in Tirupati.

Communist Party of India (CPI) secretary K. Narayana flayed the TTD officials and the local police for not working in unity, leading to the stampede.

TTD Trust Board former Chairman and YSR Congress Party (YSRCP) Tirupati district president Bhumana Karunakar Reddy blamed the lack of coordination between TTD's vigilance sleuths and the district police for the incident. "The officials reviewed the arrangements for the last ten days, but botched up the execution part," he said.

Former Minister for Tourism and Culture R.K. Roja called it a failure of the alliance government and demanded criminal cases should be filed on those found responsible for the stampede. In a veiled reference to Deputy Chief Minister K. Pawan Kalyan, who

had vowed to stand up for 'Sanatana Dharma', Ms. Roja wondered where the 'Sanatana warrior' had gone when the deaths happened in the first-of-its-kind stampede in Tirupati.

BJP leader P. Naveen Kumar Reddy called it gross failure of the TTD in estimating the devotee inflow for 'Vaikunta Ekadasi'. He wanted the **National Human Rights Commission (NHRC)** to take up the case suo motu and launch investigation.

## Wrongful conviction: Family seeks justice

<https://timesofindia.indiatimes.com/city/patna/wrongful-conviction-family-seeks-justice/articleshow/117091044.cms>

Jan 9, 2025, 08.23 PM IST

Sasaram: Rohtas police will present Nathuni Pal before the court for further legal action on Friday, SP Roshan Kumar said on Thursday. He added that the local police are preparing a detailed report outlining Pal's 16-year journey, which began in his native village, Devaria in the Akodhigola police station area, and spanned across Punjab and Jhansi, Uttar Pradesh.

Pal, 50, was believed to have been kidnapped, murdered and buried by his family members in 2008. However, after 16 years, it was revealed that Pal was alive. It led to the wrongful imprisonment of four family members.

According to SP Kumar, Pal's travel to Punjab was linked to his mental weakness. In the case, the informant — Pal's uncle — has since passed away. Years ago, all the accused, Vimlesh, Bhagwan, Satendra Pal, and Rati Lal, were acquitted by a local court after the prosecution failed to present sufficient evidence regarding the kidnapping, murder and burial charges.

Jeetendra Pal, the brother of the accused, has announced plans to approach the **National Human Rights Commission** and the Patna high court, seeking action against the police officers and witnesses involved in the case. "We are also seeking compensation for the trauma our family endured during the period we spent in jail," Jeetendra said.

Jeetendra also demanded legal action against the alleged eyewitnesses who claimed to have seen his brother fleeing with Pal's body.

## **NHRC seeks report on Bengaluru senior citizen's suicide following treatment denial**

<https://www.uniindia.com/nhrc-seeks-report-on-bengaluru-senior-citizen-s-suicide-following-treatment-denial/india/news/3364182.html>

New Delhi, Jan 9 (UNI) Taking suo motu cognisance of the reported suicide of a senior citizen following denial of treatment under the Ayushman Bharat scheme by a government-run hospital in Bengaluru, the National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notices to senior official

According to NHRC sources, the notices were sent to the Secretary of the Ministry of Health and Family Welfare and the Chief Secretary of the state. The Commission has called for a detailed report on the matter within four weeks.

“The reports are expected to include the current status of the implementation of the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) senior citizen scheme in Karnataka and other States and Union Territories,” the NHRC said.

According to a media report, a 72-year-old man committed suicide on 25th December 2024 after the State Government-run Kidwai Memorial Institute of Oncology in Bengaluru declined to provide him the Rs. 5 lakh cover under the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY), despite his enrollment in the scheme.

Reportedly, the hospital denied the benefit to the senior citizen, citing the lack of State government orders regarding the scheme's implementation.

“A few more cases regarding the problems faced by beneficiaries of the AB PM-JAY scheme for senior citizens have also been mentioned in the news report,” the NHRC noted. The Commission observed that the contents of the media report, if true, raise serious concerns regarding the violation of human rights.

“The Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PM-JAY) senior citizen scheme has been designed to ensure access to quality medical care for senior citizens, especially those unable to afford hospital bills, specialized treatments, and medicines. If senior citizens are being denied the benefits of a scheme meant for their welfare, it may constitute a violation of their right to health, which is essential for a life with dignity,” it added. UNI PSP SSP Tags: #NHRC seeks report on Bengaluru senior citizen's suicide following treatment denial

## NHRC ने बुजुर्ग के 'आत्महत्या' करने के मामले में केंद्र, कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया

<https://www.timesnowhindi.com/india/aaj-ki-taza-khabar-10-january-2025-hindi-news-live-latest-news-aaj-ka-hindi-samachar-live-updates-liveblog-117100642>

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने केंद्र और कर्नाटक सरकार को उन खबरों पर नोटिस जारी किया है, जिनमें कहा गया है कि पिछले साल दिसंबर में बेंगलुरु के एक सरकारी अस्पताल द्वारा कल्याणकारी योजना का लाभ देने से इनकार करने पर 72 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। एनएचआरसी ने कहा कि अगर खबर की सामग्री सही है, तो यह मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने एक बयान में कहा कि एनएचआरसी ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। बयान में कहा गया है कि रिपोर्ट में कर्नाटक, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी शामिल किए जाने की भी उम्मीद है। एनएचआरसी ने कहा कि उसने "मीडिया में आई एक खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है कि 72 वर्षीय व्यक्ति ने 25 दिसंबर, 2024 को आत्महत्या कर ली, क्योंकि कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य सरकार द्वारा संचालित किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पांच लाख रुपये का कवर देने से इनकार कर दिया।"



## Mizoram : विधवाओं की बेहतरी के लिए विधवा प्रकोष्ठ की स्थापना की

<https://jantaserishta.com/local/mizoram/mizoram-widow-cell-set-up-for-betterment-of-widows-3758134>

**Ashish verma 9 Jan 2025 2:58 PM GMT**

**Mizoram मिजोरम :** [विधवाओं](#) को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मिजोरम की समाज कल्याण और जनजातीय मामले, महिला और बाल विकास मंत्री लालरिनपुई ने गुरुवार, 9 जनवरी को अपने कार्यालय में 'विधवा प्रकोष्ठ' का उद्घाटन किया। इस पहल ने मिजोरम को ऐसे प्रगतिशील उपाय अपनाने वाले चुनिंदा भारतीय राज्यों में शामिल कर दिया है।

विधवा प्रकोष्ठ की स्थापना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की उस अनुशंसा के अनुरूप है, जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर सरकारों से विधवाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाने का आग्रह किया गया है। प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर में एकीकृत इन प्रकोष्ठों का उद्देश्य पूरे राज्य में विधवाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है।

मंत्री लालरिनपुई ने इस बात पर जोर दिया कि विधवा प्रकोष्ठ मौजूदा कल्याणकारी पहलों को बढ़ाने और विधवाओं के भविष्य के लिए व्यापक योजनाएँ तैयार करने का प्रयास करता है। उन्होंने राष्ट्रीय और समुदायों दोनों में विधवाओं की देखभाल को सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में महत्व दिया। विधवा प्रकोष्ठ को विधवाओं के अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें सांत्वना देने और ज़रूरतमंदों को मार्गदर्शन देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है।

[विधवा प्रकोष्ठ](#) के उद्देश्यों में बेरोज़गार विधवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना, सरकारी कल्याण योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुरूप मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करना और कानून के तहत उनके अधिकारों को बनाए रखने के लिए कानूनी सहायता प्रदान करना शामिल है।